



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Ms
28/10/97

सं० 507]
No. 507]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 1997/भाद्र 12, 1919
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 1997/BHADRA 12, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1997

आय-कर

का. आ. 636 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-झक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 के नियम 11 ड. क के साथ पठित धारा 80-झक की उपधारा (2) के खंड (iv) के उपखंड (ग) के अधीन निम्नलिखित जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

1. गोड्डा	बिहार
2. गुमला	बिहार
3. अररिया	बिहार
4. गदचिरोली	महाराष्ट्र
5. मचेपुरा	बिहार
6. सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश
7. दुमका	बिहार
8. मांडला	मध्य प्रदेश
9. खगरिया	बिहार
10. किशनगंज	बिहार
11. मालदा	पश्चिमी बंगाल
12. प्लामू	बिहार

13.	फूलबनी	उड़ीसा
14.	मधुबनी	बिहार
15.	कालाहांडी	उड़ीसा
16.	जहानाबाद	बिहार
17.	सहरसा	बिहार
18.	पश्चिमी दिनाजपुर	पश्चिमी बंगाल
19.	नवादा	बिहार
20.	बहराइच	उत्तर प्रदेश
21.	सीतामढ़ी	बिहार
22.	साहबगंज	बिहार
23.	मुर्शिदाबाद	पश्चिमी बंगाल
24.	कूच बिहार	पश्चिमी बंगाल
25.	बंकुरा	पश्चिमी बंगाल
26.	पन्ना	मध्य प्रदेश
27.	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश
28.	महाराजगंज	उत्तर प्रदेश
29.	जेलोर	राजस्थान
30.	औरंगाबाद	बिहार
31.	पूर्वांचलमार्ग	बिहार
32.	बांदा	उत्तर प्रदेश
33.	बाड़मेर	राजस्थान
34.	पुरनिया	बिहार
35.	बस्तर	मध्य प्रदेश
36.	सीवान	बिहार
37.	वैशाली	बिहार
38.	बस्ती	उत्तर प्रदेश
39.	सरगुजा	मध्य प्रदेश
40.	घमोली	उत्तर प्रदेश
41.	जैसलमेर	राजस्थान
42.	लोहरदगा	बिहार
43.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश
44.	उत्तरकाशी	उत्तर प्रदेश
45.	चूरू	राजस्थान
46.	चायानाद	केरल
47.	इदुक्की	केरल
48.	अलपाहगुड़ी	पश्चिमी बंगाल
49.	अल्मोड़ा	उत्तर प्रदेश
50.	पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश
51.	टिहरी गढ़वाल	उत्तर प्रदेश
52.	दी डग्स	गुजरात
53.	बांसवाडा	राजस्थान

स्पष्टीकरण :—इस अधिनियम के प्रयाजनों के लिए, में जिले, तारीख 4 अक्टूबर, 1994 की पिछड़े जिलों की पहचान के लिए अध्ययन समूह की रिपोर्ट में वर्णित जिलों के समान है और वे 1991 की जनगणना रिपोर्ट में यथाउल्लिखित जिलों पर आधारित है। जहां धारा 80-इक के प्रयोजनों के लिए कोई विनिर्दिष्ट जिला औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले के रूप में 1991 की जनगणना के पश्चात् या तो विभाजन या अन्यथा पुनर्गठित किया गया है, वहां इस जिला में आने वाले क्षेत्र जो 1991 की जनगणना रिपोर्ट में विद्यमान है, इस नियम के लिए अर्हक होगा।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1994 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों को प्रोत्साहन देने का उपबंध करने के लिए धारा 80-इक का वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधन किया गया था। पिछड़े जिलों की शनाख्त करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अक्टूबर, 1994 में अपनी रिपोर्ट दी थी जिसका दूसरी समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट 1996 में प्रस्तुत की थी। अब, सरकार ने 1-10-1994 से औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को अधिसूचित करने का विनिश्चय कर लिया है।

इस अधिसूचना का भूतलक्षी प्रवर्तन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

[फ. सं. 142/20/94-टी. पी. एल. (पीटी III)/सं.-10404]

जय राज काजला, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 1997

INCOME-TAX

S. O. 636 (E).—In exercise of powers conferred by section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government specifies the following districts as industrially backward districts under sub-clause (c) of clause (iv) of sub-section (2) of section 80-IA read with rule 11EA of the Income-tax Rules, 1962; namely :—

1.	Godda	Bihar
2.	Gumla	Bihar
3.	Araria	Bihar
4.	Gadchiroli	Maharashtra
5.	Madhepura	Bihar
6.	Sidharthanagar	Uttar Pradesh
7.	Dumka	Bihar
8.	Mandla	Madhya Pradesh
9.	Khagaria	Bihar
10.	Kishanganj	Bihar
11.	Malda	West Bengal
12.	Palamau	Bihar
13.	Phulbani	Orissa
14.	Madhubani	Bihar
15.	Kalahandi	Orissa
16.	Jehanabad	Bihar
17.	Saharsa	Bihar
18.	West Dinajpur	West Bengal
19.	Nawadah	Bihar
20.	Bahraich	Uttar Pradesh

21.	Sitamarhi	Bihar
22.	Sahebganj	Bihar
23.	Murshidabad	West Bengal
24.	Cooch Behar	West Bengal
25.	Bankura	West Bengal
26.	Panna	Madhya Pradesh
27.	Pratapgarh	Uttar Pradesh
28.	Maharajganj	Uttar Pradesh
29.	Jalore	Rajasthan
30.	Aurangabad	Bihar
31.	East Champaran	Bihar
32.	Banda	Uttar Pradesh
33.	Barmer	Rajasthan
34.	Purnia	Bihar
35.	Bastar	Madhya Pradesh
36.	Siwan	Bihar
37.	Vaishali	Bihar
38.	Basti	Uttar Pradesh
39.	Sarguja	Madhya Pradesh
40.	Chamoli	Uttar Pradesh
41.	Jaisalmer	Rajasthan
42.	Lohardagga	Bihar
43.	Chhatarpur	Madhya Pradesh
44.	Uttarkashi	Uttar Pradesh
45.	Churu	Rajasthan
46.	Wayanad	Kerala
47.	Idukki	Kerala
48.	Jalpaiguri	West Bengal
49.	Almora	Uttar Pradesh
50.	Pithoragarh	Uttar Pradesh
51.	Tehri Garhwal	Uttar Pradesh
52.	The Dangs	Gujarat
53.	Banswara	Rajasthan

Explanation : For the purpose of this notification, the districts correspond to the districts mentioned in the Report of the Study Group on Identification of Backward Districts dated 4th October, 1994 and are based on districts as they stood in the Census Report of 1991. Where a district specified as an industrially backward district for the purposes of section 80-IA is reorganised, either by spilt or otherwise, after the Census Report of 1991, all the areas comprised in the district as it existed in the Census Report of 1991 will qualify for the purpose of this rule.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of October, 1994.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Section 80-IA was amended by the Finance Act, 1994 so as to provide incentive to new industrial undertakings set up in industrially backward districts. A committee was constituted to identify backward districts. Committee gave its report on October, 1994, which was reviewed by another Committee and submitted its report in 1996. The Government have now taken a decision to notify the industrially backward districts w.e.f. 1-10-1994.

The retrospective operation of this notification will not adversely affect any person.

[F. No. 142/20/94/TPL(PT.III)/No.-10404]

JAI RAJ KAJLA, Under Secy.